

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

सामान्य अवधारणा के लिए, राष्ट्रीय पेंशन देखें। यह लेख में बहुत ही समस्याएं हैं। कृपया इसे बेहतर बनाने में मदद करें या चर्चा पृष्ठ पर इन मुद्दों पर चर्चा करें। (इन टेम्पलेट संदेशों को कैसे और कब हटाएं जानें) इस लेख को अद्यतन करने की आवश्यकता है। (अगस्त 2016) सत्यापन के लिए इस लेख हेतु अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। (अगस्त 2016) इस लेख की निष्पक्षता पर विवाद है। (दिसंबर 2013) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) परियोजना प्रबंधन पेंशन निधि का प्रकार स्थान मुंबई, कोलकाता देश भारत वेबसाइट www.npskra.nsdl.co.in नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) भारत में एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली है। पीपीएफ और ईपीएफ की तरह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत में एक ईईईई (एकजम्प-एकजम्प-एकजम्प) उपकरण है, जहां पूरा कोष परिपक्वता पर कर से बच जाता है और पूरी पेंशन निकासी राशि कर मुक्त होती है। [१] NPS ने 1 जनवरी 2004 के बाद शामिल होने वाले अपने सभी कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ पेंशन को रोकने के लिए भारत सरकार के निर्णय के साथ शुरू किया था। इस योजना को शुरू में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए डिज़ाइन किया गया था, इसे भारत के सभी नागरिकों के लिए खोला गया था। 2009 में 18 और 60. [2] इसकी समग्र संरचना में एनपीएस संयुक्त राज्य अमेरिका की 401 (के) योजनाओं के करीब है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) (चक्का मुनि बालाजी गणेश कमेटी की सिफारिशों के आधार पर), प्रशासित और विनियमित (जटुरू साहित्य समिति)। [३] [४] [५] [६] 10 दिसंबर 2018 को, भारत सरकार ने NPS को भारत में एक पूरी तरह से कर-मुक्त साधन बना दिया, जहां संपूर्ण कॉर्पस परिपक्वता पर कर से बच जाते हैं, 40% वार्षिक कर-मुक्त भी हो गए। [7] रुपये में कटौती के लिए एनपीएस के टियर -2 के तहत योगदान धारा 80 सी के तहत कवर किया गया है। आयकर लाभ के लिए 1.50 लाख, बशर्ते तीन साल की लॉक-इन अवधि हो। [8] [9] [१०] [११] ११ एनपीएस में बदलाव को आयकर अधिनियम, 1961 में बदलाव के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा, जो

कि भारत के 2019 के केंद्रीय बजट में वित्त विधेयक के माध्यम से होने की उम्मीद है। [12] NPS 60% की सीमा तक EEE सीमित है। [13] 40% अनिवार्य होना चाहिए वार्षिकी खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है, जो लागू टैक्स स्लैब में कर योग्य है। [14]

एनपीएस में योगदान से आयकर अधिनियम की धारा 80 सी, धारा 80CCC और धारा 80CCD (1) के तहत कर छूट प्राप्त होती है। 2016 से शुरू होकर, धारा 80CCD (1 बी) के तहत 50,000 रुपये का अतिरिक्त कर लाभ एनपीएस के तहत प्रदान किया जाता है, जो धारा 80 सी की 1.5 लाख रुपये से अधिक की छूट है। [15] [16] [17] निजी कोष प्रबंधक एनपीएस के महत्वपूर्ण भाग हैं। [18] [19] [20] एनपीएस को सबसे अच्छा टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में से एक माना जाता है, क्योंकि मैच्योरिटी के समय कॉरपस को 40% कर मुक्त कर दिया गया था और इसे इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) से ठीक नीचे रखा गया था। [21]

पृष्ठभूमि

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली है जिसे भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा निर्मित पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रशासित और विनियमित किया जाता है। NPS ने भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 के बाद शामिल होने वाले अपने सभी कर्मचारियों के लिए निर्धारित लाभ पेंशन को रोकने के निर्णय के साथ शुरू किया था।

केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए डिज़ाइन किया गया था, इसे 2009 में भारत के सभी नागरिकों के लिए खोला गया था। एनपीएस भारत में एक पेंशनभोगी समाज बनाने के लिए सरकार द्वारा एक प्रयास है। इसकी समग्र संरचना में एनपीएस संयुक्त राज्य अमेरिका की 401 (के) योजनाओं के करीब है। आज, एनपीएस [22] धारा 80CCC और धारा 80CCD के तहत आसानी से उपलब्ध है और कर कुशल है। एनपीएस के तहत, कोई व्यक्ति अपने सेवानिवृत्ति के खाते में योगदान कर सकता है। साथ ही, उसका नियोक्ता व्यक्ति के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान कर सकता है। एनपीएस भारत में एक अर्ध-ईईटी साधन है, जहां 40% कॉर्पस परिपक्वता पर कर से बच जाता है, जबकि 60% कॉर्पस कर योग्य है। [23]

[24] [२५] 60% कर योग्य कोष में से 40% कर-मुक्त है क्योंकि इसे वार्षिक खरीद के लिए अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जाना है। [२६] हालाँकि, वार्षिकी आय पर कर लगेगा। शेष 20% पर अब निकासी पर स्लैब दरों पर कर लगेगा। [२ will] एनपीएस ग्राहकों को दो रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसियों की पसंद प्रदान करता है: NCRA (NSDL-CRA) और KCRA (कार्वी-CRA)। [२ [] [२ ९] 2017 के भारत के केंद्रीय बजट में, एनपीएस में समयपूर्व आंशिक निकासी के रूप में एक कर्मचारी द्वारा किए गए योगदान की 25% छूट की घोषणा की गई है। [30] यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 को प्रभावी होगा और तदनुसार, मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के संबंध में लागू होगा। [३१] [३२] एनपीएस एक बाजार से जुड़ा वार्षिकी उत्पाद है। [३३]

नियामक ढांचा 1999 में भारत सरकार ने भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा से संबंधित नीतियों की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना OASIS ("वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा के लिए एक संक्षिप्त रूप") शुरू की। OASIS रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने सशस्त्र बलों को छोड़कर, केंद्र / राज्य सरकार की सेवा के लिए नए प्रवेशकों के लिए एक नई परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली की शुरुआत की, जो परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली की मौजूदा प्रणाली को प्रतिस्थापित करती है। 23 अगस्त 2003 को, अंतरिम पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की स्थापना भारत सरकार द्वारा एक संकल्प के माध्यम से की गई थी, ताकि योजनाओं के लिए ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए पेंशन फंडों की स्थापना, विकास और विनियमन करके बुढ़ापे की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। पेंशन फंड के लिए और जुड़े मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए। " पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 19 सितंबर 2013 को पारित किया गया था और 1 फरवरी 2014 को अधिसूचित किया गया था, इस प्रकार भारत में पेंशन क्षेत्र के लिए नियामक के रूप में PFRDA की स्थापना की। हालांकि, कर्मचारी भविष्य निधि, जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा संचालित पेंशन फंड, और म्यूचुअल फंड कंपनियों जैसे PFRDA के दायरे से बाहर अन्य संस्थाओं के साथ काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। 22 दिसंबर 2003 को भारत सरकार द्वारा अंशदायी पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किया गया था, जिसे अब 1 जनवरी 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) नाम दिया गया है। NPS को 1 मई 2009 से प्रभावी रूप से देश के सभी नागरिकों के लिए विस्तारित किया गया था, स्व-नियोजित पेशेवरों और असंगठित क्षेत्र के अन्य

लोगों को स्वैच्छिक आधार पर शामिल करना। आर्किटेक्चर पारंपरिक वित्तीय उत्पादों के विपरीत, जहां एक कंपनी द्वारा सभी कार्य (बिक्री, संचालन, सेवा, निधि प्रबंधन, डिपॉजिटरी) किए जाते हैं, एनपीएस एक असंबद्ध वास्तुकला का अनुसरण करता है जहां मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण को दूसरे से अलग कर दिया गया है। यह असहनीयता न केवल ग्राहक को मूल्य श्रृंखला के माध्यम से सेवा के अपने प्रदाताओं को मिलाने और मैच करने की अनुमति देती है, सबसे अच्छा विकल्प चुनती है, बल्कि यह मिसिंग की घटनाओं पर भी अंकुश लगाती है। एनपीएस आर्किटेक्चर में एनपीएस ट्रस्ट शामिल है, जिसे ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सौंपा गया है, सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियां (सीआरए) जो डेटा और रिकॉर्ड्स, प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) को संग्रह, वितरण और सर्विसिंग आर्म्स, पेंशन फंड मैनेजर्स (पीएफएम) के रूप में रखता है। सब्सक्राइबर्स के निवेश के प्रबंधन के लिए, निधि प्रबंधकों द्वारा खरीदी गई संपत्तियों की देखभाल करने के लिए एक संरक्षक, और बैंकिंग कार्यों के प्रबंधन के लिए एक ट्रस्टी बैंक। 60 वर्ष की आयु में ग्राहक पेंशन वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एसपी) को खरीदना चुन सकता है। एनपीएस निवेशक दो पेंशन फंड प्रबंधकों का विकल्प नहीं चुन सकते हैं, न ही एक वर्ष से पहले किसी अन्य पेंशन फंड में बदल सकते हैं। 2017 में, PFRDA ने एनपीएस में प्रवेश की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी। [34]

एनपीएस में पेंशन फंड मैनेजर (पीएफएम) की संख्या बढ़कर 9 हो गई है: [35] [36]

एसबीआई पेंशन फंड
एलआईसी पेंशन फंड
यूटीआई सेवानिवृत्ति समाधान
एचडीएफसी पेंशन फंड
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड
कोटक पेंशन फंड
रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड
बिड़ला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लि।

एसबीआई पेंशन फंड भारत में सबसे बड़ा पेंशन फंड मैनेजर (पीएफएम) है और प्रबंधन (एयूएम) स्तर के तहत इसकी संपत्ति 61,000 करोड़ रुपये है। [37] वर्तमान में, एनपीएस में फंड मैनेजर की पसंद या निवेश आवंटन के मामले में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का कोई कहना नहीं है, क्योंकि दोनों सरकार द्वारा तय किए गए हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सभी एनपीएस योगदान समान रूप से वितरित किए जा रहे हैं

सार्वजनिक क्षेत्र के तीन फंड मैनेजर: एलआईसी पेंशन फंड, एसबीआई पेंशन फंड और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस। वर्तमान सीआरए एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एनसीआरए) और कार्वी कंप्यूटर शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड (केसीआरए) हैं। सभी प्रमुख वाणिज्यिक बैंक, दलाल और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड PoP की भूमिका निभाते हैं। ग्राहक उनमें से किसी एक को चुन सकता है। ग्राहकों के लिए सात फंड मैनेजर और आठ एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर हैं। पेंशन फंड प्रबंधकों द्वारा दी जाने वाली चार प्रकार की निवेश योजनाओं में ग्राहक पूरी तरह से या संयोजन में निवेश कर सकता है। ये हैं: स्कीम ई (इक्विटी) जो 75% तक इक्विटी भागीदारी की अनुमति देता है, यह शेयरों में निवेश किया जाता है। स्कीम सी (कॉर्पोरेट ऋण) जो केवल 100% तक के उच्च-गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करता है। स्कीम जी (सरकार / गिल्ट बॉन्ड) जो केवल 100% तक के सरकारी बॉन्ड में निवेश करती है। स्कीम ए (वैकल्पिक निवेश) जो 5% तक की अनुमति देता है (केवल सक्रिय विकल्प के साथ निजी क्षेत्र के ग्राहक के लिए नए जोड़े गए परिसंपत्ति वर्ग) वैकल्पिक रूप से, सब्सक्राइबर डिफॉल्ट स्कीम का विकल्प चुन सकता है, जबकि उसके पोर्टफोलियो से रिटायरमेंट के लिए बचे समय के अनुसार, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी बॉन्ड के अनुपात के लिए हर साल रिबेल किया जाता है। एनपीएस अपने ग्राहकों को दो प्रकार के खाते प्रदान करता है: टियर I: प्राथमिक खाता, जो एक पेंशन खाता है जिसमें संचित धन के निकासी और उपयोग पर प्रतिबंध है। सभी टैक्स ब्रेक जो एनपीएस ऑफ़र केवल टीयर I खातों पर लागू होते हैं। टियर II: स्कीम में कुछ तरलता लाने के लिए, PFRDA एक टियर II खाते की अनुमति देता है, जहां पहले से मौजूद टियर I खातों वाले ग्राहक जब चाहें तब पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। एनपीएस टियर II एक निवेश खाता है, जो विशेषताओं में म्यूचुअल फंड के समान है। [3 is] स्वैच्छिक बचत खाते (जिसे टियर- II खाता भी कहा जाता है) में

योगदान केवल सब्सक्राइबर द्वारा किया जा सकता है, किसी तीसरे पक्ष द्वारा नहीं। [३९] PFRDA ने 2016 में NPS में नई सुविधाएँ पेश की हैं, जिसमें जीवनचक्र के लिए अधिक विकल्प शामिल हैं:

आक्रामक जीवन चक्र निधि (LC-75) जो ग्राहकों को 35 वर्ष की आयु तक 75% तक इक्विटी एक्सपोजर की अनुमति देता है। यह 20 के निवेशक के लिए अधिक उपयुक्त है। [41] 25% इक्विटी जोखिम के साथ रूढ़िवादी जीवन चक्र फंड, पुराने निवेशकों के लिए अनुकूल हो सकता है। [42]

स्वचालित रूप से जीवनचक्र निधि।

नियामक एनपीएस पर उपलब्ध इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्ड के मौजूदा मेनू में एक नया परिसंपत्ति वर्ग वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) जोड़ता है।

कौन शामिल हो सकता है

भारत का एक नागरिक, चाहे निवासी या गैर-निवासी निम्नलिखित शर्तों के अधीन, एनपीएस में शामिल हो सकते हैं:

एनपीएस (पीओपी-एसपी) के लिए पीओपी के प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस-सर्विस प्रोवाइडर-अधिकृत शाखाओं के लिए उसकी आवेदन जमा करने की तारीख के रूप में ग्राहक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

ग्राहकों को आपके ग्राहक पंजीकरण फॉर्म में विस्तृत रूप में आपके ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों का पालन करना चाहिए।

अन-डिस्क्रेडिट इंसॉल्वेंट और अनसेफ माइंड के व्यक्तियों को नहीं होना चाहिए।

सब्सक्राइबर बेस

दिसंबर 2016 तक, ग्राहकों की संख्या बढ़कर 1.41 करोड़ हो गई थी। एनपीएस एयूएम (प्रबंधन के तहत संपत्ति) दिसंबर 2016 तक बढ़कर 1,61,016 करोड़ रुपये हो गई। कुल एनपीएस एयूएम का 88% हिस्सा सरकारी क्षेत्र के लिए है, दोनों केंद्रीय और राज्य कर्मचारी, जो ग्राहकों की संख्या का 35 प्रतिशत हिस्सा हैं। [43] मार्च 2016 तक, एनपीएस टियर II

सेगमेंट का कुल एयूएम 197 करोड़ रुपये है। एनपीएस टियर II के पास 54,000 रुपये के औसत बैलेंस के साथ 34,620 ग्राहक हैं। [44]

खाता खोलना

ईएनपीएस के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया

ई-एनपीएस 2015 में शुरू हुआ, केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उपलब्ध दो विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करके एनपीएस खाता ऑनलाइन खोला जा सकता है: [४५] [४६]

एक, आधार-आधारित केवाईसी, जिसमें आपको एक ओटीपी के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा जो आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर पर भेजा जाएगा। एक बार खुद को प्रमाणित करने के बाद, केवाईसी

आधार डेटाबेस से जानकारी ली जाएगी। यदि आपने आधार-आधारित पंजीकरण का चयन किया था, तो आपको एक स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। आप किसी भी बैंक के खाते से नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना निवेश कर सकते हैं। यदि आप

आधार-आधारित केवाईसी चुनते हैं, तो आपको भौतिक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और भेजने की जरूरत नहीं है। आप बस ई-साइन कर सकते हैं। एनपीएस फॉर्म को प्रिंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे आपने ऑनलाइन भरा था और प्रिंटआउट 90 दिनों के भीतर केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को जमा करना था। आगे बढ़ने का दूसरा तरीका केवाईसी

प्रमाणीकरण चरण को पूरा करने के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) और बैंक खाता विवरण देना है। ऑफ़लाइन प्रक्रिया ऑफ़लाइन उद्घाटन के लिए, किसी को PFRDA द्वारा नियुक्त किए गए किसी भी पॉइंट ऑफ़ प्रेज़ेंस (POPs) पर जाना होगा। [४ has] निकासी 60 वर्ष की

आयु से पहले एनपीएस में समय से पहले निकासी की आवश्यकता वार्षिकता में राशि का 80% पार्किंग है। [48] 60 साल से पहले कोई भी 20 प्रतिशत लाश निकाल सकता है लेकिन

उसे 80 प्रतिशत धनिया के साथ वार्षिकी खरीदनी चाहिए। [49] 2016 में, NPS ने निर्दिष्ट

कारणों के लिए 25% तक के अंशदान को वापस लेने की अनुमति दी, यदि यह योजना कुछ शर्तों के साथ कम से कम 3 वर्ष पुरानी है। यदि एकत्रित पेंशन INR 2,00,000 से कम है तो पूरी राशि निकाल सकते हैं। [उद्धरण वांछित] कर लाभ एनपीएस में निवेश निम्नानुसार कर लाभ

के लिए पात्र है: तक रु। धारा 80CCD (1) के तहत 150,000। बेसिक सैलरी के 10% पर अतिरिक्त लाभ मिलता है। धारा 80C, धारा 80CCC और धारा 80CCD (1) के तहत लाभ 150,000 रुपये पर छाया हुआ है। धारा 80 सीसीडी (1 बी) के तहत 50,000 रुपये तक का योगदान। यह धारा 80CCD (1 बी) के तहत कर लाभ के ऊपर और ऊपर है। [50] राशि के संदर्भ में किसी भी ऊपरी टोपी के बिना मूल और डीए का 10% तक नियोक्ता सह-योगदान, धारा 80CCD के तहत कर्मचारियों के हाथों में कर मुक्त आय है